लोकमत समाचार
तमसो मा ज्योतिर्गमय

प्रकृति को बुरा-भला न कहो. उसने अपना कर्तव्य पूरा किया, तुम अपना करो. ■ मिल्टन

संपादकीय

'सरपंच पति' संस्कृति पर रोक कैसे लगे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी बात कही है कि पंचायतों में 'सरपंच पति' की संस्कृति बंद होनी चाहिए. पंचायत राज दिवस पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 'सरपंच पतियों' को पंचायतों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. कानून ने महिलाओं को काम करने का अधिकार दिया है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए. यह स्थिति सिर्फ पंचायतों तक सीमित नहीं है. नगरपालिकाओं में भी 'पतियों' की ही चलती है. स्थानीय निकायों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाने से बेचारे 'पति महोदय' अब क्या करें? कहीं-कहीं तो आधी से अधिक सीटों पर महिलाएं ही काबिज हैं. औरंगाबाद का एक उदाहरण सामने है जहां 59 महिलाएं हाल ही में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में जीत कर आई हैं. यह तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा बल है. ऐसे में हमेशा राजनीतिक जमीन तलाशने वाले पतियों को जगह नहीं मिलने से अब पत्नियों का ही सहारा रह गया है. इसके लिए उन पर व्यंग्य बाण चलाएं या छींटाकशी करें, आदत से लाचार पतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता. अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? इसके लिए कहीं न कहीं राजनीतिक दल ही दोषी हैं. अगर सचमुच महिलाओं को राजनीति में सक्रिय करना है तो उन्हें पूरी तरह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. पंचायत राज में महिलाओं के लिए समान सीटें मुहैया कराई गई हैं तो उन्हें पंचायतों में काम करने का प्रशिक्षण भी अच्छी तरह दिया जाए ताकि वे पतियों को अपने कामकाज में दखल देने से रोक पाएं. महिलाएं राजनीति में आई हैं तो उन्हें आगे बढ़ कर कामकाज निपटाना चाहिए. कहीं-कहीं ऐसा भी है कि नहीं चाहते हुए भी पति की इच्छा रखने के लिए राजनीति में आना पड़ रहा है. ऐसे में 'सरपंच पति' संस्कृति पनपना स्वाभाविक है. यह संस्कृति अक्सर उन पंचायतों या स्थानीय निकायों में अधिक देखी जाती है जहां पति एक दबंग राजनीतिज्ञ हो. उसे राजनीति करनी है, अपने बलबूते न सही, पत्नी का सहारा तो है. कहीं-कहीं महिलाओं में संकोच और झिझक से भी इस संस्कृति को बढ़ावा मिला है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर महिला सशक्तिकरण का कोई मतलब ही नहीं रह जाता. इससे कामकाज भी प्रभावित होता है. ऐसी स्थिति में महिला आरक्षण का उद्देश्य भी सफल नहीं हो पाएगा. जहां स्थानीय निकायों में महिलाएं ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं वहां पतियों से सलाह-मशविरा करना वक्त का तकाजा तो है, लेकिन महिलाओं को भी अपनी हैसियत का एहसास होना चाहिए, वरना वे मुखौटा ही कहलाएंगी. अब चूंकि बात प्रधानमंत्री ने की है इसलिए भाजपा से ही इसकी शुरुआत हो जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है. प्रधानमंत्री के संदेश पर गंभीरता से अमल करने की उम्मीद कम से कम भाजपा से तो की ही जा सकती है. दूसरे दलों को भी इस संस्कृति से अवश्य बचना चाहिए. ■■

गंजा

वह छठी कक्षा से मेरे साथ पढ़ता था. हमेशा प्रथम आता था. फिर भी सारा कॉलेज उसे सनकी मानता था. एक प्रोफेसर ने एक बार उसे रजिस्टर्ड पागल भी कहा था. कभी बिना मूंछों की दाढ़ी रख लेता था तो कभी मक्खी छाप मूंछें. तरह-तरह के टोप पहनना भी उसके शौक में शुमार था.

लघुकथा

अनुराग शर्मा

पुराना परिचय होते हुए भी मुझे उससे कोई खास लगाव नहीं था. सच तो यह है कि उसके प्रति अपनी नापसंदगी मैं कठिनाई से ही छिपा पाता था. पिछले कुछ दिनों से वह किस्म-किस्म की पगड़ियां पहने दिख रहा था. लेकिन तब तो हद ही हो गई जब कक्षा में वह अपना सिर घुटाए हुए दिखा. एक सहपाठी प्रशांत ने चिढ़कर कहा, ''सिर तो आदमी तभी घुटाता है जब जूं पड़ जाएं या जब बाप मर जाए.''

वह उठकर कक्षा से बाहर आ गया. जीवन में पहली बार वह मुझे उदास दिखा. प्रशांत की बात मुझे भी बुरी लगी थी सो उसे झिड़ककर मैं भी बाहर आया. उसकी आंख में आंसू था. उसकी पीड़ा कम करने के उद्देश्य से मैंने कहा, ''कुछ लोगों को बात करने का सलीका ही नहीं होता है. उनकी बात पर ध्यान मत दो.''

उसने आंसू पोंछा तो मैंने मजाक करते हुए कहा, ''वैसे बुरा मत मानना, बाल बढ़ा लो, सिर घुटाकर पूरे कैंसर के मरीज लग रहे हो.''

मेरी बात सुनकर वह मुस्कराया. हम दोनों ठठाकर हंस पड़े.

आज उसका सैंतालीसवां जन्मदिन है. सिर घुटाने के बाद भी कुछ महीने तक मुस्कुराकर कैंसर से लड़ा था वह. ■■

चैनल या चैन, अधिग्रहण या ग्रहण?

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

बेमौसम बादल की तरह चैनल के दर्शन की तारीख आगे बढ़ गई. हवा का रुख और मोदी मुहूर्त देखना जरूरी होगा. इसलिए गरजने-बरसने की तारीख और समय की कोई पूर्वसूचना नहीं दी जा सकती. वैसे ठीक ही हुआ. सरकार की 100 करोड़ की कृपा से शुरू होने जा रहे 'किसान टी.वी. चैनल' के पहले ग्रास में आत्महत्या कर रहे किसानों का खून-मांस देखकर देश-दुनिया घबराकर हाहाकार करने लगती. दावा जो भी हो, याददाश्त कमजोर हो रही हो, भारत सरकार के पिछले 5 वर्षों के बजट उठाकर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि मनमोहन सरकार ने भी 'किसान चैनल' की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया था. लेकिन मनमोहन राज के दो मंत्रियों के टकराव में चैनल का पहिया अटक गया. तब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे. बजट में किसान चैनल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान ग्रामीण विकास मंत्रालय के खाते में रख दिया गया था, क्योंकि राहुल स्टार मंत्री जयराम रमेश के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय था. उन्हें अपने ढंग से 'किसान नेता' की इमेज बनाने की चिंता थी. लेकिन इमरजेंसी युग से 'सूचना तंत्र' के उपयोग की सही दावेदार समझी जाने वाली अंबिका सोनी के पास सूचना प्रसारण मंत्रालय था. उनके पास लाजवाब तर्क थे-'दूरदर्शन' के पास इतना बड़ा ढांचा है और भारतीय भाषाओं के चैनलों का पूरा गुलदस्ता है. इसी के साथ 'किसान चैनल' का एक फूल और जोड़ देना पर्याप्त होगा. इस तरह 'किसान चैनल' की फाइलें सूचना-प्रसारण, ग्रामीण विकास मंत्रालयों और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच चक्कर लगाती रहीं. बाद में दोनों मंत्री बदल गए. फिर भी मनमोहन सिंह फैसला नहीं कर सके.

बहरहाल असली 'किंग' नरेंद्र मोदी ने आते ही आपत्तियों की पुरानी टिप्पणियों को कूड़े में डालकर 'मन की बात' मनवाने के लिए किसान चैनल की घोषणा कर दी. बेचारे नए-पुराने कांग्रेसी नेता, प्रवक्ता, सांसद यह भी याद नहीं रख सके कि 'किसान चैनल' का प्रस्ताव उनका अपना था. अपनी विफलता को याद करके ज्यादा आंसू बहाने से आंखों में दर्द और दिल में आग लगती है. इसीलिए 26 मई को मोदी राज की 'रिकार्ड ऐतिहासिक सफलता के एक वर्ष' का चमकीला 'रिपोर्ट कार्ड' जारी होने पर एक बिंदु 'किसान चैनल' के फैसले का भी दिखाई देगा. वैसे चैनल की जानकारी भोलेभाले महानगरीय और शहरी पाठकों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने पिछले दो महीनों में विज्ञापनों पर लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं.

नया 'किसान चैनल' जल्द या देरी से शुरू होने पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है. किसानों को चैन, सुकून, समृद्धि मिलने की इच्छा और चिंता सबको होनी चाहिए. ग्रामीण इलाकों के 'महानतम विकास लक्ष्य' के नाम पर मोदी सरकार द्वारा लाया गया भूमि अधिग्रहण विधेयक-कानून-अध्यादेश का पहिया भी राजनीतिक दलदल में फंस गया. मजेदार बात यह है कि भूमि अधिग्रहण कानून का पहला विधेयक भी मनमोहन सिंह सरकार को भाजपा के समर्थन से ही पारित करवाना था. यही नहीं उस कानून की एक-एक धारा, उपधारा पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ.मुरली मनोहर जोशी और लोकसभा की वर्तमान अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की छाप होने का दावा किया जाता रहा है. अब 'मोदी मुहर' वाले भूमि अधिग्रहण कानून के कुछ नए प्रावधानों पर बवेला मचा हुआ है. ईमानदार शूरवीर कर्ण के रथ की तरह भाजपा सरकार का रथ भी रास्ते में फंस गया है. यों देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले वर्षों के दौरान किसानों से अधिग्रहीत लगभग 35 लाख एकड़ जमीन खाली पड़ी है. केंद्र और राज्य सरकारें कम से कम उस पर विकास की गाड़ी आगे धकेलने की कोशिश कर सकती हैं. भूमि अधिग्रहण कानून में सबसे घातक 'ग्रहण' किसान की स्वीकृति लिए बिना उसकी जमीन सरकार द्वारा लिया जाना है. इस 'ग्रहण' की आग न किसान सह सकता है और न ही कोई राजसत्ता मनवा सकती है. हमारे गांव में घर आंगन, खेत-खलिहान की सीमा वाली पांच गज जमीन के लिए लाठियां, गोलियां चल जाती हैं. पूरी महाभारत एक इंच जमीन तक नहीं देने के मुद्दे पर हुई है. उस देश में आप किसान की जमीन उसकी मर्जी के बिना कैसे ले सकते हैं. अन्यथा मेरे अपने गांव, कस्बे में अपने दादाजी की जमीन रेलगाड़ी का रास्ता बनाने वाली रेल की पटरियों और बांध बनाने के लिए नानाजी की खेती की जमीन ही नहीं बड़े पूरे मकान की जमीन सरकार को लगभग दान की तरह दे दी गई थी. भारतीय गांवों में परंपरा से उदार लोग जमीन दान-उपहार में दिया करते थे. बांध के लिए जमीन देने वाले लाखों लोगों ने नए गांव ही विकसित कर दिए. लेकिन सत्ता का डंडे के बल पर जमीन छीन लेना ग्रामीणों से कभी बर्दाश्त नहीं होता.

> भूमि अधिग्रहण कानून में सबसे घातक 'ग्रहण' किसान की स्वीकृति लिए बिना उसकी जमीन सरकार द्वारा लिया जाना है. इस 'ग्रहण' की आग न किसान सह सकता है और न ही कोई राजसत्ता मनवा सकती है.

विडंबना यह है कि भूमि अधिग्रहण के ग्रहण की दशा में किसानों की असली समस्याओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है. एक बार जरा याद कीजिए या पिछले साल के अखबार के पन्ने पलट लीजिए और उपलब्ध हों तो फरवरी से मई 2014 के दौरान प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदीजी के धुआंधार भाषण के वीडियो देख लीजिए. पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़ोत इलाके में किसानों की भीड़ को संबोधित करते हुए मोदीजी ने गन्ने का खरीदी मूल्य 500 रुपया दिलाने का वायदा कर दिया. ऐसे भाषण बड़ोत से बेंगलुरु और मुंबई-नासिक, नागपुर तक पहुंच गए. लेकिन चुनावी रैलियों के लिए भाषण के मुख्य मुद्दे तैयार करने वाली हार्वर्ड रिटर्न टीम को गन्ने के उत्पादन, खरीदी मूल्य, चीनी मिलों के दांव-पेंच और हालत का अंदाज ही नहीं था. अब हालत यह है कि किसानों से खरीदी का नया मूल्य 500 रुपया तो बहुत बड़ी बात है, 250 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदे गए गन्ने का बकाया नहीं मिल पा रहा है. भाजपा के नेता-प्रवक्ता उत्तर प्रदेश, बिहार की सरकारों के सिर पर पत्थर मारते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकते हैं. लेकिन 'गुजरात मॉडल' की ही सरकार के लिए घड़ा किसके सिर पर फोड़ेंगे? गुजरात में कांग्रेस की नैया और पतवार ही गायब कही जा सकती है और उनके नेताओं की मत सुनिए. लेकिन वहां तो भाजपा का अपना दक्षिण गुजरात किसान संघ किसानों का नेतृत्व कर सरकार का विरोध कर रहा है. मोदीजी के अपने प्रिय सूरत के बारडोली इलाके में किसानों ने चीनी के सैकड़ों बोरे फेंककर विरोध व्यक्त किया है. क्योंकि उनके लिए इस बार केवल 1500 रुपए प्रति टन खरीदी मूल्य की दरों से गन्ना खरीदने की घोषणा हुई है. जबकि पिछले साल 2100 रुपए प्रति टन पर खरीदी हुई थी.

इस समय महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है. किसानों को बकाया नहीं मिल रहा और आत्महत्याएं निरंतर बढ़ रही हैं. वही सरकार ने चीनी मिलों को दो हजार करोड़ रुपए बिना ब्याज के उधार देने की घोषणा कर दी है. इस साल महाराष्ट्र में करीब 925 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है. जबकि पिछले साल 700 लाख टन का उत्पादन हुआ था. राज्य सरकार ने चीनी मिलों पर बकाया 850 करोड़ रु. का परचेस टैक्स भी माफ कर दिया है. मतलब, चीनी मिलों को बचाने के प्रयास हैं फिर केंद्र सरकार किसानों को उनकी उपज गन्ने, धान, गेहूं का सही खरीदी मूल्य तथा पुराना बकाया दिलवाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की कोशिश क्यों नहीं करती?

इसी तरह भारी वर्षा से फसल नष्ट हो जाने के कारण बैंक कर्ज माफ करने तथा तत्काल मुआवजा देने के लिए समयसीमा तय कर भाजपा-संघ अपने करोड़ों सदस्यों को मदद के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ा देते? ■■

तालिबान के पास मिसाइल!

अवधेश कुमार
जाने-माने पत्रकार

आजकल घटनाएं इतनी तेजी से घटती हैं कि कई बार अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, जबकि वो गहरा नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखती हैं. ऐसी ही एक घटना है पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा मिसाइल निर्माण संबंधी दावा. निस्संदेह, लंबे समय से दुनिया में आतंकवादी संगठनों द्वारा विनाशकारी हथियार पाने या निर्माण करने की आशंकाएं उठाई जाती रही हैं. आतंकवादी संगठनों ने इस दिशा में काम किया और कुछ सफलताएं भी प्राप्त कीं तभी तो वे दुनिया में चारों ओर विध्वंस का कोहराम मचाने में सफल हो रहे हैं. पर पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने इन सबसे अलग मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण का जो दावा किया है वह दुनिया के लिए चेतावनी है कि खतरा अब ज्यादा आसन्न हो गया है. इसकी कल्पना शायद अभी किसी ने नहीं की थी. टीटीपी के खिलाफ लगातार हमले करने वाले अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी इसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया. इस नाते यह दुनिया के लिए हक्का-बक्का करने वाली खबर है. हालांकि टीटीपी के दावे पर कई प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं. यह अस्वाभाविक नहीं है. चूंकि इसके पूर्व ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सहसा इस पर विश्वास करना कठिन है. तो हम क्या मानें?

टीटीपी ने मिसाइल परीक्षण के दावे को सही ठहराने के लिए एक वीडियो और बयान जारी किया है. इस वीडियो में मिसाइल को तैयार करते हुए और उसे सफलतापूर्वक लांच करते हुए दिखाया गया है. टीटीपी के प्रवक्ता मुहम्मद खुरासानी ने दावा किया है कि इस मिसाइल को जैसे हालात हों उसके मुताबिक आसानी से जोड़ा और खोला जा सकता है. वीडियो के अनुसार इसकी मुख्य विशेषता इसकी डिजाइन है. यानी इसे उसी तरह आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है जैसे आम राइफल, रॉकेट.... आदि. इसके अलग-अलग अंगों को ले जाकर जहां से छोड़ना हो वहां कुछ ही मिनट में जोड़ दिया जा सकता है. अगर यह सच है तो इसे तकनीकी विशेषज्ञता का प्रमाण भी मानना होगा.

अगर वाकई टीटीपी ने मिसाइल बना लिया है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हमारे यानी भारत के लिए यह सबसे ज्यादा चिंता का विषय है. पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा राज्य पाकिस्तान तालिबान का गढ़ माना जाता है. इससे भारत की सीमा करीब 600 किलोमीटर दूर है. यह अमेरिका द्वारा तालिबान को ध्वस्त करने के सपने पर कुठाराघात जैसा है. वैसे हाल के दिनों में इस खबर की पुष्टि होती रही है कि तालिबान युद्ध तकनीक के क्षेत्र में अपने सुरक्षित ठिकाने पर लगातार उन्नयन की ओर अग्रसर है. उसकी तकनीकी टीम कुछ घातक हथियार बनाने में सक्षम हुई भी है. मसलन, उसने आत्मघाती बेल्ट, आत्मघाती वाहन, हैंड ग्रेनेड, एंटी-जैमर डिवाइस आदि हथियार स्वयं विकसित कर लिए हैं. किसी आतंकवादी संगठन के लिए ये सामान्य उपलब्धियां नहीं हैं. तो इसका अर्थ क्या है? जरा विडंबना देखिए. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा के दौरान तालिबान ने वीडियो एवं बयान जारी कर मिसाइल परीक्षण में कामयाब होने का दावा किया है. क्या चीनी राष्ट्रपति ने इसका संज्ञान नहीं लिया होगा? आखिर उन्होंने आतंकवाद से संघर्ष करने के लिए करोड़ों डॉलर का समझौता किया है.

> अगर वाकई तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने मिसाइल बना लिया है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हमारे यानी भारत के लिए यह सबसे ज्यादा चिंता का विषय है.

टीटीपी की स्थापना दिसंबर 2007 में हुई. बैतुल्ला महसूद के नेतृत्व में 13 गुटों ने संगठित होकर जिहाद की तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला लिया. यह संगठन वहां प्रतिबंधित है, पर इतने सालों से लड़ रहा है. मुल्ला फजलुल्लाह इस समय इसका नेता है जिसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है. पिछले वर्ष 16 दिसंबर को टीटीपी ने ही पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर बड़ा हमला करके 141 लोगों की मौत के घाट उतारा जिसमें 132 बच्चे थे. उसके बाद इसके खिलाफ ज्यादा सघन अभियान चला है. सेना दावा कर रही है कि ड्रोन हमलों में लश्कर-ए-इस्लाम (एलआई) और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों समेत आतंकियों के टॉप कमांडर मारे गए हैं. प्रश्न है कि अगर उसकी इतनी ही क्षति हो गई तो फिर वह इतने घातक हथियार बनाने और मिसाइल प्रक्षेपित करने का दावा करने तक की स्थिति में कैसे आ गया. इसके लिए तो बाजाब्ता सारी सुविधाओं से लैस बहुत बड़ा सुरक्षित स्थान चाहिए. जाहिर है, यह स्थिति पाकिस्तान के दावों को संदेहों के घेरे में ले आता है.

यह विचार करने वाली बात है कि आखिर इतने लंबे समय से अमेरिका हमला कर रहा है. स्वयं पाकिस्तानी सेना कई सालों से इस आतंकी संगठन से जूझ रही है. इसके बावजूद यदि उसकी ताकत बढ़ रही है तो दुनिया कब तक प्रतीक्षा करेगी? अब तो दुनिया को मान लेना होगा कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकवाद का अंत नहीं कर सकता, बल्कि उनकी ताकत जिस ढंग से बढ़ रही है उससे दुनिया को खतरा है.

लेकिन क्या वह दूसरे देशों के साथ मिलकर इनका मुकाबला करने को तैयार होगा. चीन से वह संसाधन तो ले लेगा, लेकिन प्रत्यक्ष उनके साथ मिलकर लड़ने को नहीं. कारण, इससे उसका पाखंड सामने आ जाएगा. जिस आतंकवाद को उसने स्वयं पैदा किया, पाला पोसा उसके दो भाग को आज भी वहां सेना एवं आईएसआई का पूरा समर्थन है. वह है, भारत केंद्रित आतंकवाद एवं अफगानिस्तान पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए खड़े किए गए समूह. ये दोनों उसकी ऐसी भयावह कमजोरियां हैं जिनके रहते वह आतंकवाद का खात्मा कैसे कर सकता है? इसलिए आज आतंकवादी समूह मिसाइल परीक्षण का दावा कर रहे हैं. कल वो डर्टी बम बना लेंगे, जिनसे एक दो शहरों को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है. उनकी बढ़ती शक्ति से पाकिस्तान के एटमी हथियारों की सुरक्षा का प्रश्न फिर से उभर गया है. ■■

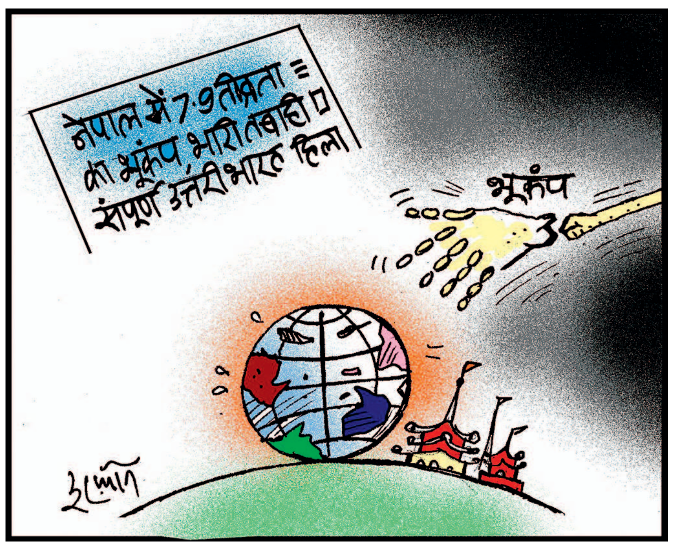

जोखिम उठाकर हासिल किया लक्ष्य

स्मार्ट स्ट्रीट
बिजनेसमैन

प्रकाश बियाणी
कॉर्पोरेट इतिहासकार

फैमिली रन बिजनेस को प्रोफेशनल बनाकर 15 साल में 36 गुना (200 करोड़ से 7,224 करोड़ रुपए) करने वाले उद्यमी हैं पंकज पटेल. सन 1952 में उनके पिता रमणभाई पटेल ने इंद्रवदन मोदी के साथ केडिला लेबोरेटरीज की स्थापना की थी. 1995 में यह भागीदारी खत्म हुई तो केडिला ब्रांडनेम दोनों भागीदारों को मिला. इंद्रवदन मोदी की कंपनी का नाम हो गया केडिला फार्मास्युटिकल्स. रमणभाई पटेल ने नामकरण किया केडिला हेल्थ केयर. पंकजभाई पटेल ने इसमें 'जायड्स' जोड़कर नया नाम दिया जायड्स केडिला. यूनानी देवता 'जीउस' से जन्मा है जायड्स. 2000 में यह कंपनी बीएसई में केडिला हेल्थ केयर के नाम से सूचीबद्ध हुई, जिसके सीएमडी हैं पंकजभाई पटेल.

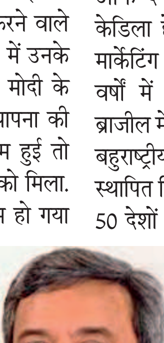

पंकज पटेल

एम. फार्मा की पढ़ाई करके पंकजभाई पटेल सन 1976 में पिता के कारोबारी सहयोगी बन गए थे. 1995 में उन्होंने पुश्तैनी फार्मा बिजनेस के सूत्र संभाले, तब कंपनी का टर्नओवर था 200 करोड़ रुपए और ओवरहेड्स व वेतन खर्च था 400 करोड़ रुपए. पंकजभाई पटेल ने लक्ष्य तय किया - सन 2000 में 1,000 करोड़ रुपए टर्नओवर.

मानवीय नेत्रों से साढ़े तीन गुना तीव्र नेत्र क्षमता वाला पक्षी ईगल लंबी दूरी से अपने लक्ष्य को चिह्नित कर लेता है. ऐसी ही सूक्ष्म निगाहों वाले पंकजभाई ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दो जोखिम उठाए. उन्होंने तय किया कि वे अपना खुद का फार्मास्युटिकल्स प्लांट स्थापित करेंगे, ताकि मैन्युफैक्चरिंग पर उनका संपूर्ण नियंत्रण रहे और वे क्वालिटी ड्रग्स बना सकें. दूसरे, भारतीय दवा उद्योग के दिग्गज जब जेनेरिक दवाएं (पेटेंट समयावधि से मुक्त दवा) बना रहे थे, तब पंकजभाई लीक से हटकर दवा डिस्कवर करना चाहते थे.

अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना के लिए पंकजभाई ने परिवार के निवासी मकान को छोड़कर अन्य संपदा और भूमि बेचने का निर्णय लिया तो मित्र-परिजनों ने कहा- अकारण जोखिम उठा रहे हो. उत्पादों की आउटसोर्सिंग करो. पर 'ईगल आई' के धनी पंकज भाई नहीं माने. 1997 में 50 करोड़ रुपए निवेश करके उन्होंने स्टेट-ऑफ-द-आर्ट प्लांट स्थापित किया. केडिला हेल्थ केयर की मैन्युफैक्चरिंग व मार्केटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए विगत 15 वर्षों में अमेरिका, स्पेन, अफ्रीका और ब्राजील में 15 कंपनियां खरीदीं. चार दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त वेंचर्स स्थापित किए. इस स्ट्रेटेजी का सुफल है कि 50 देशों में सक्रिय केडिला हेल्थ केयर के आज दुनिया में 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं.

पंकजभाई पटेल कहते हैं कि अगले दशक में भारत भी ड्रग डिस्कवरी डेस्टिनेशन होगा, तब यहां फार्मा वॉर में वही बचेगा, जिसके पास अपने पेटेंट अधिकार होंगे. केडिला हेल्थ केयर इसकी तैयारी कर रहा है. कंपनी के 11 हजार कर्मचारियों में 1000 चिकित्सा विज्ञानी हैं, जो सतत शोध अनुसंधान ही कर रहे हैं.

पंकजभाई पटेल ने कंपनी का दैनंदिन कामकाज नौ वरिष्ठ एक्जिक्यूटिव्स को सौंप दिया है. जॉन हॉपकिन्स मेडिकल सेंटर से पीएचडी डिग्री प्राप्त उनके पुत्र श्रविल केडिला हेल्थ केयर के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. पंकजभाई पटेल अब ज्यादा समय अपनी आर एंड डी टीम के साथ व्यतीत करते हैं. समाज से जो मिला, उसे वे अपने अंदाज में लौटा रहे हैं. अहमदाबाद में उन्होंने दो स्कूल बनवाए हैं. गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वे हेड हैं. उन्होंने एक अस्पताल और मेडिकल स्कूल बनाने में भी सहयोग प्रदान किया है.

बेस्ट फॉर्मामेन, इनोवेटर अवार्ड और इंडियन बिजनेस लीडर जैसे अवार्ड्स से सम्मानित 61 वर्षीय पंकजभाई पटेल 3.2 बिलियन डॉलर (करीब 200 अरब रुपए) निजी संपदा के साथ देश के 26वें सबसे धनी उद्यमी हैं. उनका कहना है कि व्यापार से संपदा का सृजन होता है. संपदा से व्यापार नहीं फलता-फूलता है. ■■

तोल बोल

मैं एक घंटे तक भाषण देने वाला था, लेकिन गजेंद्र की मौत के बाद मैंने 15-20 मिनट में ही भाषण खत्म कर दिया. भाषण जारी रखना मेरी गलती थी.

■ अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

राहुल गांधी के आने से सुरक्षित केदारनाथ का संदेश देश-विदेश में गया है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चार धाम यात्रा पर आने का न्यौता दूंगा.

■ हरीश रावत, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

पाठकों के पत्र

भूमि अधिग्रहण कानून

भूमि अधिग्रहण कानून किसानों के खिलाफ है. ऊंची कीमतों पर केंद्र सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को जमीन बेच देगी. यदि यह विधेयक राज्यसभा में पास हो जाता है तो कानून बन जाएगा, क्योंकि लोकसभा में इसे पारित किया जा चुका है. किसान व मजदूर खेती पर निर्भर हैं. किसानों को उनकी भूमि से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए. जैसा कि वर्तमान में आदिवासियों के पास भूमि का अधिकार है वैसा ही किसानों को भी मिलना चाहिए. यदि ऐसा प्रावधान होता कि आदिवासी अपनी जमीन को बेच सकता है तो वह गरीब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कब का अपनी जमीन को बेच चुका होता. कानून के अनुसार आदिवासियों के पास भूमि तो सुरक्षित है. जिससे वह अपनी जीविका चला रहा है. वर्तमान भूमि अधिग्रहण कानून किसानों के हित में नहीं है. यदि किसी दूसरे काम के लिए किसानों से भूमि लेकर बेची जाती है तो इससे उद्योगपतियों को ही ज्यादा फायदा होगा.

■ बी.सी. उके, सिवनी

इतिहास पर नजर 26 अप्रैल

आज ही के दिन 1962 में पहली बार एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान ने चांद की सतह को छुआ था. रेंजर-4 चांद की सतह पर उतर तो गया पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण चित्र नहीं भेज सका. इससे पहले तत्कालीन सोवियत संघ 1959 में ही अपना अंतरिक्ष रॉकेट चंद्रमा की सतह पर उतार कर इतिहास रच चुका था. अमेरिकी अंतरिक्ष रॉकेट रेंजर-4 का प्रक्षेपण 23 अप्रैल को केप कार्निवाल केंद्र से किया गया था. हालांकि इस अभियान का मकसद चांद की सतह के चित्र भेजना था, पर प्रक्षेपण के दो घंटे बाद ही अंतरिक्ष यान की बिजली आपूर्ति ठप हो गई. बिजली आपूर्ति ठप हो जाने के बाद रेंजर-4 का धरती से संपर्क टूट गया. वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान में मौजूद एक छोटे से रेडियो ट्रांसमीटर पर ध्वनि तरंगें भेज कर पता लगाया कि यान चंद्रमा पर उतर चुका है. आखिरकार 31 जुलाई 1964 को रेंजर-7 अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक चांद की सतह के चित्र भेजे. ■■

- ■1755-रूस का पहला विश्वविद्यालय राजधानी मॉस्को में खोला गया.
- ■1841-बॉम्बे गैजेट अखबार पहली बार रेशम के कपड़े पर प्रकाशित किया गया.
- ■1920-प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का निधन.
- ■1926-जर्मनी और रूस ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए.
- ■1993-औरंगाबाद में बोइंग-737 विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 56 लोग मारे गए.

gñWmnH$ gnmXH$: nd. Odmhabmb XS>m
M`a_Z, E{S>Q>m{a`b ~mS>© : {dO` XS>m
E{S>Q>a-BZ-Mr\$: amOD> XS>m
gnmXH : {dH$mg {_l ★
★ nr. Ama. ~r. H$mZyZ H$ AZgma gnU gnmXH$s` Xm{`Ëd
H$ {bE {Oå_Xma.

© लोकमत समाचार _ àH$m{eV g^r gm_J«r H$m gdm©{YH$ma bmH$_V _r{S>`m àm`dQ> {b. H$ nmg gw[ajV h.
bmH$_V _r{S>`m àm`dQ> {b. H$ {bE _ÐH$ Ed àHmeH बालाजी मुले Ûmam bmH$_V _r{S>`m àm. {b., ßbmQ> H$. 192, 207, 208 E_. AmB. S>r. gr. BÝS>{ñQ´>`b E[a`m, ~Qr~mar, ZmJnya _{ÐV Ed bmH$_V ^dZ n. Odmhabmb Zhê$ _mJ, ZmJnya _ àH$m{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaÜd{Z : 0712-2423527 (7 bmBÝg) \¡$Šg : 6618555
Email : gnmXH$s` : lsedit.ngp@lokmat.com {dkmnZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com